हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 10 अंक : 275 | सोमवार, 02 मई, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी है यात्रा : सतपाल महाराज

8

अवैध निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज का असली खेल, जानिए

सलीम सैफी
न्यूज वायरस नेटवर्क

जो निर्माण विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बाय लॉज के विरुद्ध निर्माण है वो ₹अवैध निर्माण₹ है,ये हम सबको पता है लेकिन बिल्डिंग बाय लॉज ही ₹अवैध निर्माण₹ का मुख्य कारण है ये हम समझना नही चाहते,सिंगल लाइन है बाय लॉज के हिसाब से निर्माण होगा तो वैध है वरना अवैध,वाह भाई वाह, हर गरीब को घर,ये सपना आप कैसे गरीब को दिखा सकते है जब आप 50,100,150,200 मीटर साइज के प्लॉट वालो को बिल्डिंग बायलॉज के नाम पर लगभग आधा प्लॉट निर्माण से मुक्त रखोगे तो हर गरीब को घर का सपना कैसे पूरा होगा,उम्रभर की कमाई से खरीदा गया प्लॉट आधा खाली छोड़ेगा तो बचेगा क्या,धनिया बोएगा या गाजर ये तो प्राधिकरण का बिल्डिंग बायलॉज बनाने वाले ही बता सकते है,सरकारी जमीन पर रैंप बनाए,भवन बनाए या कुछ

सवाल

- प्राधिकरण के अधिकारी/इंजीनियर और बाबू कैसे हो जाते है करोड़पति, कैसे
- 50,100,150,200 मीटर के प्लॉट हो या 5000 मीटर ,50,000 मीटर के सबके लिए एक ही व्यवस्था क्यों
- मुख्य मार्गो से अलग हटकर सेटबैक और रोड वाईडिंग के नाम पर छोटे प्लॉट धारकों पर ज़ुल्म की व्यवस्था क्यों
- व्यवसायिक भवन हो या टाउनशिप सभी शिकार होते है अवैध निर्माण के नाम पर,पारदर्शी व्यवस्था के नाम पर अव्यवहारिक व्यवस्थाएं क्यों
- प्राधिकरणों में ऑनलाइन के नाम पर ऑफलाइन व्यवस्थाओं का मकड़जाल क्यों
- कंपाउंडिंग के नाम पर सर्किल रेट से दुगुना शुल्क व्यवस्था,हर परिवार को घर के सपने पर कुठाराघात तो नही

और बनाए तो समझ आता है कि वो अवैध निर्माण है,टूटना चाहिए, कार्येवाई होनी चाहिए लेकिन अपनी ही भूमि के 70-80 या 90% भाग पर निर्माण करना, कवर करना अवैध कैसे , भाई बिल्डिंग बायलाज अवैध क्यों नही हो सकते,छोटे प्लॉट्स के संदर्भ में भी और बड़ों के संबंध में भी

अवैध निर्माण जिसे कहा जाता है दरअसल वो बिल्डिंग बाय लॉज के नाम पर सरकार का वो जुल्म है जिसमे किसी भी निर्माण का आधे से ज़्यादा भू भाग निर्माण से वंचित कराए जाने को बाध्य किया जाता है,अगर कोई अपनी ही भूमि पर 70 या 80% प्रतिशत भाग कवर कर लेता है तो उसे सरकार अवैध करार देती है जो एक जुल्म का पर्यायवाची है,किसी का प्लॉट साइज 50 मीटर हो,100 मीटर हो या 150 -200 मीटर उससे भी जबरन बाय लॉज के नाम पर,सेट बैक और रोड वाईडिंग के नाम पर 50% तक भूमि खाली छुड़वाई जाती है,अब आप सोचो 50,100,150,200 मीटर वालो के पास क्या बचा और अगर प्लॉट कॉर्नर का हो तो कुछ भी नही बचा,कवर्ड एरिया निकालो कितना निकला और यही नियम 500 मीटर,5000 मीटर या ज्यादा पर होता है वहा समझ आता है की जमीन साइज बड़ा है ,आप गरीब आदमी पर भी बाय लॉज के नाम पर जुल्म कर रहे है और अमीर के साथ व्यापार कर रहे, क्यों, उसे अपनी ही लगभग 50% प्रतिशत भूमि में से कुछ भाग कवर करना है अगर उसने कवर करके निर्माण कर भी लिया तो कंपाउंडिंग के नाम पर उसे सर्किल रेट से दुगुने रेट पर प्रति मीटर निर्माण शुल्क सरकार को देना है,जो बहुत ज्यादा होता है,व्यवहारिक नही होता, कुल मिलाकर बाय लॉज व्यवहारिक न होने की वजह से गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी की कमर टूट जाती है और प्राधिकरण के अधिकारियों/ इंजीनियरों को पैसा कमाने का मजबूत आधार मिल जाता है जिसे नाम दिया जाता है ₹अवैध निर्माण₹ और अमीर आदमी भी यही करने को मजबूर होता है,यही वजह है जो आवास विभाग को मलाईदार पोस्टिंग में तब्दील करता है,जरूरत है बाय लॉज में छोटे और बड़े प्लॉट में व्यवहारिक परिवर्तन की, व्यवस्थाओं की जिससे कि अपने छोटे छोटे प्लॉट्स में ज्यादा से ज्यादा कवर्ड एरिया/ कवरेज मिल सके ,आप और हम खामख्वाह खुश हो रहे है कि सरकार अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला रही है , व्यवहारिक सोच होनी चाहिए,बाय लॉज त्रुटिपूर्ण है,व्यवहारिक नही है, उनमें व्यवहारिक परिवर्तन जरूरी है,सोचो ज़रा क्या अवैध है ,क्या वैध,बाय लॉज को गौर से पढ़िए अपने आप पता चल जायेगा JE,AE या अन्य प्राधिकरणकर्मी चंद दिनों में करोड़ों में कैसे पहुंच जाते है,असली खेल बाय लॉज का का,सरकार इस तरफ़ व्यवहारिक सोच रखे।

सुरकंडा देवी मंदिर रोप वे का हुआ उद्घाटन, दर्शन हुआ आसान

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

स्टेट एयर क्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार की सुबह तय समय पर दिल्ली से देहरादून नही लौट सके। बाद में मुख्यमंत्री धामी सुबह प्रस्तावित कार्यक्रमों को रद्द कर स्टेट हेलीकॉप्टर से ही सीधे दिल्ली से सुरकंडा देवी मंदिर नई टिहरी में रोप वे के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सुरकण्डा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 30 अप्रैल 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने गए थे। मुख्यमंत्री धामी को 1 मई (रविवार) की सुबह 8:30 पर देहरादून पहुंचना था लेकिन एन वक्त पर एयरक्राफ़्ट में आई दिक्कत के कारण मुख्यमंत्री धामी समय पर देहरादून नहीं पहुंच सके। जिसके चलते उन्हें सुबह के समय प्रस्तावित क्रार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा।

बाद में मुख्यमंत्री धामी स्टेट हेलीकॉप्टर से सीधे दिल्ली से सुरकंडा देवी मंदिर नई टिहरी में रोप वे के उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करने के लिए रवाना हो गए। जहां उन्होंने रोपवे का शुभारंभ किया।

मंत्री एक रंग अनेक : हंसिया, हॉकी के बाद मंत्री रेखा आर्य ने दिखाया बैडमिंटन में हुनर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क (आशीष तिवारी)

खेल मंत्री रेखा आर्या बीते कुछ दिनों से फील्ड में बेहद सक्रीय नज़र आ रही हैं। कभी खेतों में गेहूं की बाली काटती दिखाई देती हैं तो कभी हॉकी टर्फ पर खिलाडियों को हॉकी की बारीकी और खेल की अहमियत समझाती दिखाई देती हैं। इस बीच बच्चों के संग खाना खाकर रियलिटी चेक करती तस्वीर भी सबने देखी है

शनिवार को एक कार्यक्रम में देहरादून के बहुददेशीय क्रीड़ा हाल परेड ग्राउंड में जब मंत्री जी ने बैडमिंटन थामा तो लोग बड़े उत्सुकता से उनके हुनर को देखते नज़र आये। आपको बता दें कि बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में मिनिस्टर रेखा आर्य शामिल हुयी थीं।

इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि अगर तन मन को स्वस्थ रखना है तो खेल जरूरी है, उन्होंने कहा कि खेल से सम्पूर्ण शरीर फिट रहता है , और मन शांत रहता है जिससे हम अपने काम पर एकाग्रता से काम कर सकते हैं । और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। मंत्री आर्या जी ने कहा कि खेल के लिए ही वो आजकल जगह जगह जाकर स्टेडिम, इंडोर स्टेडिम की दशा देख रही हैं, ताकि खेलों को सही दिशा मिल सके ।उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने के लिए वो खेल स्कॉलरशिप, खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सामग्री ताकी उन्हें कहीं दूसरी जगह जाकर हीन भावना से ग्रसित ना होना पड़े , इस दिशा में काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों को कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए फाइलें चलनी नही दौड़नी चाहिए। और सभी को आश्वस्त किया गया कि हमारा विभाग सदैव खिलाड़ियों के साथ है और विभाग के जरिये खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जाएगी।

अब लोगों को इंतज़ार रहेगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का अगला कौन सा हुनर लोग देखेंगे और अब उनका काफिला किस तरफ औचक निरीक्षण के लिए दौड़ने वाला है ।

बरसेंगे मेघा : ठंडी पड़ेगी गर्मी की तपिश, ये है अनुमान

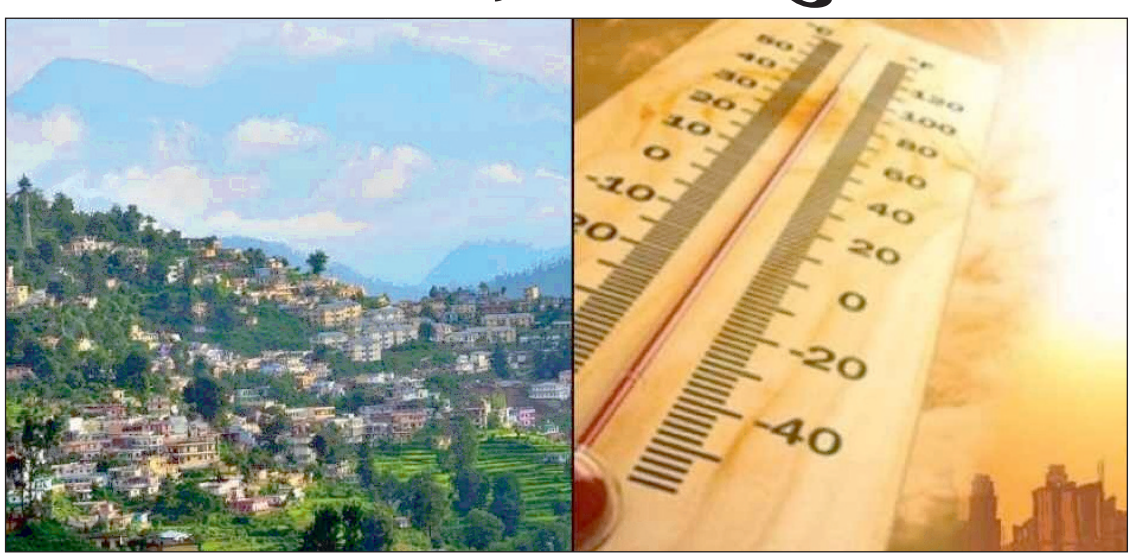

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश झेल रहे उत्तराखंड के लोगों के साथ ही वनाग्नि से धधक रहे जंगलों को बचाने में जुटे वन विभाग के कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। अगर मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी को मान लें तो मौसम बदलने वाला है और पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो गया है।

मतलब आप ये समझिये कि हवाओं के दबाव के चलते जहां तीन मई को राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश की संभावना है, वहीं अगले 48 घंटे में राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही पर्वतीय इलाकों में एक बार स्थानीय हवाओं का दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में तीन मई को मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरे राज्य में बारिश होने की पूरी संभावना है। फिलहाल मौसम का बदला मिजाज अगले 48 घंटे में भी देखने को मिलेगा।

अनुमान है कि 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और दून के आसमान में जहां बादल छाए रहेंगे, वहीं पर्वतीय इलाकों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि बारिश के साथ ही तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में सावधान रहे और इंतज़ार करें कि कब आपको गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी।

चम्पावत में 2 मई को आयोजित होगा ''किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी'': गणेश जोशी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग की एक अहम बैठक में कृषि एवं औद्यानिक गतिविधियों के समग्र विकास हेतु रणनीति तैयार करने एवं कृषकों को पारदर्शितापूर्ण लाभान्वित करने के लिए पी0एम0यू0 के गठन किया जाने, किसान एप तैयार किया जाने तथा ''किसान भागेदारी प्राथमिकता हमारी'' कार्यशालाओं के तहत किसान फसल बीमा कार्यशालाओं के आयोजन जैसे विषयों पर निर्देश दिए गए।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन में किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कृषकों को भविष्य में भी समयान्तर्गत धनराशि प्रदान की जाए। अधिक से अधिक किसानों को कृषक हित में संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाय।

निर्देश देते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि पर्वतीय जनपदों में कृषि एवं औद्यानिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद/विकासखण्ड स्तर पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायें। जिसमें ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत समूहों (मुख्य रूप से महिलाओं) को भी प्रतिभाग कराया जाय।

इस क्रम में 2 मई, को जनपद चम्पावत में ''किसान भागेदारी प्राथमिकता हमारी'' के अन्तर्गत फसल बीमा कार्यशाला तथा अन्य किसान योजनाओं की जानकारी देने तथा किसानों को ऑन द स्पॉट योजना का लाभ देने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया जाय। जिसमें कृषि/उद्यान विभाग के समस्त रेखीय विभागों के साथ-साथ ग्राम्य विकास विभाग की भी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।

इस बैठक में डा0 राम बिलास यादव, अपर सचिव, कृषि, आनन्द स्वरूप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0, डा0 एच0एस0 बवेजा, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, गौरीशंकर, निदेशक, कृषि उपस्थित रहे।

अस्पतालों से रेफर करने की बीमारी खत्म होगी : डॉ धन सिंह रावत

रूद्रप्रयाग एवं नैनीताल को मिला उत्तम जिला अस्पताल का अवार्ड

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

■ स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की 94 चिकित्सा इकाईयों को दिया कायाकल्प सम्मान

जनपद रूद्रप्रयाग एवं नैनीताल के जिला अस्पतालों को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 के लिये उत्तम चिकित्सालय के कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में प्रदेश की कुल 94 चिकित्सा ईकाईयों को अलग-अलग श्रेणियों में कायाकल्प सम्मान मिला। जिनको प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने पुरस्कार की राशि का चैक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुये राजकीय जिला अस्पतालों को नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) मान्यता के लिये आवेदन करना होगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज देहरादून में एक निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेशभर की 94 चिकित्सा इकाईयों को अलग-अलग श्रेणी में कायाकल्प सम्मान से पुरस्कृत किया। जिला अस्पताल रूद्रप्रयाग एवं बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। जिसमें दोनों चिकित्सालयों को रूपये 25-25 लाख के चैक व प्रमाण पत्र दिये गये। इसी प्रकार उप जिला चिकित्सालय रूड़की को अपनी श्रेणी में प्रथम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धौलादेवी एवं गरमपानी को द्वितीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। जिसमें इन चिकित्सालयों को क्रमशः रूपये 15 लाख व रूपये 5-5 लाख के चैक प्रदान किये गये। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहिया को बेस्ट ईको फ्रेन्डली श्रेणी में प्रथम आने पर रूपये 6 लाख का चैक देकर सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस पहल के उपरांत सूबे में मातृ-शिशु मृत्युदर में कमी आने के साथ ही रोगियों के अस्पताल में रहने की अवधि तथा अस्पताल से उत्पन्न संक्रमण की दर में कमी आई। यही नहीं इस कार्यक्रम से प्रदेश के अस्पतालों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुई जिसका लाभ यहां आने वाले मरीजों को मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी दो वर्ष के भीतर राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालय नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) मान्यता के लिये आवेदन करेंगे। प्रथम चरण में जिला एवं उप जिला अस्पतालों को एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने के लिए मानकों को पूरा करने को कहा गया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक खजान दास ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल एवं टेक्निशियनों की आवश्यकतानुसार तैनाती की जानी चाहिए, ताकि मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ हो सके। सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने कहा कि कायाकल्प जागरूकता हेतु स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि स्वास्थ्य कार्मिकों के मध्य सकारात्मक व्यवहार स्थापित किया जा सके। उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ ही मरीजों की बेहत्तर देखभाल करने पर बल दिया। स्वास्थ्य सचिव ने जन औषधि केन्द्रों को और बेहत्तर ढंग से संचालित करने, दवाओं का पर्याप्त भण्डारण रखने के लिये मुख्य चिकित्साधिकारियों को स्वयं निगरानी करने को कहा।

एनएबीएच मान्यता के लिए आवेदन करेंगे राजकीय चिकित्सालय

जिला अस्पतालों से रैफर नहीं होंगे मरीज : डॉ0 धन सिंह रावत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कायाकल्प सम्मान समारोह से पूर्व विभिन्न जनपदों से आये मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ बैठक कर जिला एवं उप जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला एवं उप जिला अस्पतालों को रैफर सेंटर नहीं बनाया जायेगा बल्कि अस्पताल आने वाले 90 फीसदी मरीजों का उपचार वहीं पर करना होगा। इसके लिए उन्होंने जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारियों को तीन दिन में रिपोर्ट तैयार कर महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए महानिदेशालय प्रक्रिया शुरू करेगा। जबकि स्टॉफ नर्स, विभिन्न टेक्नीशियन, वार्ड ब्वाय व सफाई कर्मी के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से जनपद स्तर पर भरा जायेगा। उन्होंने कहा कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहत्तर बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जायेगा। प्रथम चरण में राजकीय मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों को सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जायेगा। जबकि दूसरे चरण में उप जिला चिकित्सालों एवं तीसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चौथे चरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बेहत्तर व सुविधा सम्पन्न बनाया जायेगा। उन्होंने राजकीय अस्पतालों के सौन्दरीयकरण व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश जनपद स्तर के अधिकारियों को दिये।

मुख्य चिकित्साधिकारियों को सौंपी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी

बैठक में सचिव स्वास्थ्य राधिका झा, महानिदेशक डॉ0 शैलजा भट्ट, निदेशक एनएचएम डॉ0 सरोज नैथानी, निदेशक डॉ0 विनीता शाह, डॉ0 मीतू शाह, डॉ0 तारा आर्य, अपर निदेशक डॉ0 भागीरथी जंगपांगी, सहायक निदेशक डॉ0 सुधीर पाण्डेय, सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी एव एसीएमओ उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में लगी आग, करोड़ों का सामना जलकर राख

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में सेना की कैंटीन में अचानक लगी आग से तीन करोड़ से अधिक का सामना जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। लेकिन शार्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है।

रविवार शाम लगभग पांच बजे जिला मुख्यालय में तैनात 11 मराठा रेजीमेंट के कैंटीन के अंदर आग लग गई। जब तक वहां तैनात जवान कुछ समय पाते, आग की लपटों से पूरे कैंटीन को अपने आगोश में ले लिया। बावजूद जवानों द्वारा अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास किया गया। साथ ही सामान को अन्यत्र शिफ्ट करते रहे। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ज्यादातर सामान को अपने चपेट में ले चुकी थी।

सूचना पर आधे घंटे में दमकल की गाड़ियां और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंचे। शाम सवा छह बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। इतना सही रहा कि आग कैंटीन के पीछे की तरफ अन्य भवनों तक नहीं पहुंची, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर,

मौके पर पहुंचे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सेना के अधिकारी व जवान शार्ट सर्किट से आग लगना बता रहे हैं। आग से काफी सामान जला रहा है। लेकिन जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी।

मामले में सेना की तरफ से अभी कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि लगभग तीन करोड़ का सामान जलकर राख हो गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

चारों धाम के कपाट खुलने और देवडोलियों के धामों को प्रस्थान का ये हैं पूरा शेड्यूल

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा 2022 कपाट खुलने का कार्यक्रम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने जानकारी देते हुए बताया है कि श्री केदारनाथ धाम कपाट 6 मई शुक्रवार समय प्रातः 6.15 पर खुलेंगेभगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली के प्रस्थान का कार्यक्रम के अंतर्गतभैरव पूजा 1 मई रविवार है। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली धाम प्रस्थान 2 मई सोमवार प्रातः 9 बजे होगा 2 मई प्रथम पडाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी प्रवास रहेगा,3 मई मंगलवार गुप्तकाशी से 8 बजे प्रातः फाटा प्रस्थान एवं प्रवास रहेगा। 4 मई बुधवार फाटा से प्रातः 8 बजे श्री गौरामाई मंदिर गौरीकुंड प्रस्थान एवं प्रवास गौरीकुंड रहेगा। 5 मई बृहस्पतिवार गौरीकुंड से प्रातः 6 बजे भगवान की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। 6 मई शुक्रवार प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खुलेंगे।

मीडिया प्रभारी ने बताया कि श्री बदरीनाथ धाम कपाट 8 मई रविवार समय 6 बजकर 25 मिनट पर खुलेंगे।

श्री बदरीविशाल देवडोली प्रस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत 6 मई शुक्रवार प्रातः9 बजे श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ से आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी एवं तेलकलश गाडू घड़ा सहित श्री बदरीनाथ धाम के रावल जी योगध्यान बदरी प्रस्थान एवं प्रवास पांडुकेश्वर रहेगा तथा 7 मई शनिवार प्रातः योग बदरी पांडुकेश्वर से आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, रावल जी सहित देवताओं के खजांची श्री कुबेर जी एवं भगवान के सखा उद्धव जी, गाडू घड़ा तेल कलश श्री बदरीनाथ धाम को पांडुकेश्वर से प्रातः 9 बजे श्री बदरीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे तथा बदरीनाथ धाम पहुंचेगे। 8 मई प्रातः 6 बजकर 25 मिनट पर शीतकाल हेतु श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

श्री गंगोत्री धाम श्री यमुनोत्री धाम कपाट खुलने का ये है शेड्यूल –

मंदिर समिति ग़गोत्री एवं मंदिर समिति यमुनोत्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि 3 मई मंगलवार दोपहर 11.15 बजे पूर्वाह्न है। श्री यमुनोत्री धाम कपाट खुलने की तिथि 3 मई मंगलवार अपराह्न दिन 12.15 बजे है यमुना जी की डोली 3 मई प्रातः शीतकालीन गद्दी स्थल खुशीमठ(खरसाली) से प्रस्थान करेगी । पवित्र हेमकुंड साहिब एवं श्री लोकपाल तीर्थ के कपाट रविवार 22 मई को को खुलेंगे।

टाइगर सफारी को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट किसने बताया ? सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने माँगा जवाब

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड का वन महकमा सुर्ख़ियों में है। आग जंगलों में सुलग रही है लेकिन इसकी धधक देहरादून से दिल्ली तक महसूस की जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रुख सीईसी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन पाखरो में टाइगर सफारी के मामले में अपनाया है वो किसी तपिश से कम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) के साथ दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों से टाइगर सफारी के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही कई बिंदुओं पर जानकारी साझा की गयी है।

कमेटी ने कार्बेट टाइगर रिजर्व के रेंज से लेकर निदेशक स्तर तक के अधिकारियों टू-डायरी भी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा कि इस टाइगर सफारी को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट किसने बताया। यही नहीं, बाघों के वासस्थल में इस तरह की अनुमति देने के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाया है। पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में पाखरो में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों को ली गई। वर्ष 2019-20 में कार्य शुरू हुआ, जिस पर लगभग चार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इस बीच टाइगर सफारी के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण की बात सामने आने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की टीम ने स्थलीय निरीक्षण में शिकायतों को सही पाया। विभागीय जांच में भी

बात सामने आई इस क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। इस मामले में शासन ने हाल में दो आइएफएस को निलंबित कर दिया था, जबकि कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक को वन मुख्यालय से संबद्ध किया।

शुक्रवार को सीईसी ने दिल्ली में बैठक में राज्य के प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डा पराग मधुकर धकाते समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डा धकाते जानकारी देते हुए बताया है कि कमेटी ने टाइगर सफारी की स्वीकृति, वन भूमि हस्तांतरण, बजट समेत तमाम बिंदुओं पर जानकारी ली। साथ ही सफारी के लिए बाघ पकडने को पांच करोड़ की राशि रखने को अनुचित बताया।

कमेटी ने पाखरो क्षेत्र के रेंज अधिकारी, डीएफओ, एसडीओ व निदेशक स्तर तक की टू-डायरी भी मांगी है। यह वह डायरी होती है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी हर माह अपनी निरीक्षण आख्या समेत कार्यों का ब्योरा मुख्यालय को देता है।

वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने यह भी पूछा कि पेड़ कटान व अवैध निर्माण के मामले में देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। इस बारे में कमेटी को पूरा ब्योरा दिया गया।

इसके अलावा कमेटी को यह जानकारी दी गई कि सफारी के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट होने जैसी कोई बात नहीं है औन न इस बारे में कभी किसी स्तर पर कोई संवाद हुआ। कमेटी ने बाघ के वासस्थल वाले क्षेत्रों में टाइगर सफारी की अनुमति के मामले में एनटीसीए व वन भूमि हस्तांतरण प्रभाग को अपनी गाइडलाइन को गंभीरता से लेने को कहा। अब देखना होगा कि प्रदेश में इस सबसे ज्वलत और चर्चित मामले में आगे और कौन से नए मोड़ आएंगे और जंगल की जाँच की आंच कहाँ तक जाएगी।

उल्टी-दस्त और पेट दर्द कोरोना के नए लक्षण : ऐसा , डॉक्टर बोले- सतर्क होने का समय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देश में कोरोना बढ़ रहा है ये खबर अब आम है लेकिन क्या आप जानते हैं इस बार इस वायरस के लक्षण थोड़ा अलग है और इसके शिकार भी नए हैं। दिल्ली, मिजोरम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार चिंता की बात यह है कि कुछ मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। छोटे बच्चों के अलावा इसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं, जो किसी न किसी दूसरी पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं। पिछले कुछ दिनों से छोटे-छोटे बच्चों में उल्टी-दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायतें मिल रही हैं। मौसम की बिमारी के साथ साथ कोरोना का भय लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ बच्चों को उल्टी दस्त के बाद कोरोना पॉज़िटिव पाया गया है।

कोविड हॉस्पिटल में नियुक्त शिशु रोग विशेषज्ञ की मानें तो इन दिनों ओपीडी में बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। इनमें उल्टी-दस्त और तेज बुखार की शिकायत ज्यादा है। वहीं, कई बच्चों में तेज पेट दर्द के भी लक्षण मिले हैं। इनमें कुछ बच्चों की जांच करवाई गई तो करीब 5 फीसदी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

उत्तराखंड में भी तेज़ी से एक बार फिर कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। देहरादून में स्कूली छात्रा में कोरोना मिला तो वहीँ दो दिन बाद कुछ वीआईपी भी कोविड की चपेट में आ गए हैं। लिहाज़ा पहाड़ भी अब सतर्क हो गया है। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी और धुप में स्कूल से बच्चे घर लौटकर पंखे ,कूलर और ऐसी में पहुँचते हैं , उसके बाद बिमारी और मौसमी बुखार की समस्या बढ़ने के आसार हो जाते हैं। लिहाज़ा परिजनों को भी सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है।

बच्चों को परीक्षा पूर्व मनोवैज्ञानिक परामर्श जरूरी : डॉ0 धन सिंह रावत

प्रत्येक विद्यालय में पीटीए का होगा गठन : डॉ0 गीता खन्ना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

किसी भी परीक्षा से पूर्व बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा। बच्चों को समझाना होगा कि परीक्षा एक उत्सव है लिहाजा किसी भी परीक्षा को एक पर्व की तरह लिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेमेस्टर अथवा वार्षिक परीक्षाओं से पूर्व प्रत्येक माह मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर बच्चों को मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाय। प्रत्येक विद्यालय में पीटीए के गठन को भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

यह बात सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दून विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित परीक्षा पर्व-04 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम से देशभर के लाखों बच्चों का मनोबल बढ़ा है। इसी प्रकार प्रदेश में भी परीक्षा से पूर्व तनाव को दूर करने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अध्यापकों एवं अभिभावकों को अपने-अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए, ताकि बच्चे परीक्षा को एक उत्सव समझकर प्रतिभाग कर सके। इसके अलावा सेमेस्टर अथवा वार्षिक परीक्षाओं से पूर्व प्रत्येक माह मासिक परीक्षाओं का आयोजन कर बच्चों को मुख्य परीक्षाओं के लिए तैयार किया जायेगा। डॉ0 रावत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायतों के बढ़ते प्रकरणों के बोझ को कम करने के लिए एक समन्वय समिति के गठन किये जाने पर बल दिया। यही नहीं उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें आयोग के सदस्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद व गीता को शामिल करने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने किया 'परीक्षा पर्व-4' कार्यक्रम का आयोजन

उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। आयोग द्वारा प्रत्येक विद्यालयों में पीटीए का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, शिक्षकों व बच्चों से संबंधी शिकायतों का समाधान पीटीए के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए आयोग द्वारा एक आउट फ्रेम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु समाज के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम को विशेष अतिथि प्रो0 सुरेखा डंगवाल, सीबीएससी के क्षेत्रीय निदेशक जयप्रकाश चतुर्वेदी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव रूपाली बनर्जी आदि ने भी सम्बोधित किया।

कार्यक्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रो0 ओ0पी0एस0 नेगी, सदस्य सचिव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग रूपाली बनर्जी, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की सदस्य पुष्पा पाटले, सदस्य उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग विनोद कपरवाण, क्षेत्रीय निदेशक सीबीएससी जयप्रकाश चतुर्वेदी, पं0 रमेश शास्त्री, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ0 मुकुल सती सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया ।

मरीजों को बिना इलाज धक्का देने के लिए नहीं बने हैं सरकारी डॉक्टर
अस्पतालों में जरूरी दवाएं पहुंचाए निदेशालय : डॉ नंदन बिष्ट

सलीम सैफी
न्यूज वायरस नेटवर्क

पुराने डीजी हेल्थ की फेयरवेल पार्टी और नए डीजी के स्वागत समारोह मे अलग ही नजारा देखने को मिला। बाहर की दवाओं के मुद्दे और स्वास्थ्य महानिदेशालय मे हुई डॉक्टरों की बैठक की वायरल वीडियो के मुद्दे पर अपनी बात रखने आए डॉक्टर एन एस बिष्ट को कुछ डॉक्टरों ने बोलने से रोकने की कोशिश की यहां तक कि एक बार तो माइक भी बंद कर दिया। फिर भी डॉक्टर एन एस बिष्ट अपनी बात कह गए, बोले कि अगर मैं खटकता हूं - तो वीआरएस दे दीजिए मगर मैं अपनी बात कह कर रहूंगा। डॉ बिष्ट ने महानिदेशालय में होने वाली डॉक्टरों की प्रपंच पूर्ण बैठको की ओर ध्यान दिलाया जिसमें स्वास्थ्य सुधारों की बातों के बजाय अस्पताल के डॉक्टरों पर छींटाकशी की जाती है तथा एक माननीय के इलाज और दवाओं को बाहर से आए लोगों के सामने अशिष्टतापूर्वक और प्रोटोकॉल तोड़कर बहस का मुद्दा बनाया जाता है।

डॉ बिष्ट ने कहा कि आपके पास अस्पतालों में 2% रोगियों के इलाज की दवाएं नहीं तो सरकारी डॉक्टरों पर किस नैतिकता से बाहर की दवाएं लिखने का लांछन लगाया जाता है और CR खराब करने की प्रक्रिया चलाई जाती है। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट की फीस और जांचों का खर्च ना उठा सकने वाले अनियंत्रित रोगो के गंभीर मरीज आते हैं उनको क्या आयरन की गोली पकड़ा कर घर भेज दिया जाए। सरकारी जिला अस्पताल में अनियंत्रित शुगर, BP, दमा, गठिया,मिर्गी, माइग्रेन, सर्वाइकल लोबैकपेन, थायराइड, बुखार, एलर्जी के मरीज ही ज्यादा आते हैं। यह लोग छोटे सरकारी अस्पतालों से पहले प्रोटोकॉल की दवा खाकर आते हैं - या प्राइवेट अस्पताल की महंगी दवा का पर्चा लेकर आते हैं। इनको देने के लिए हमारे पास दूसरे या तीसरे प्रोटोकॉल की कोई दवा मौजूद नहीं। सरदर्द, माइग्रेन, थायराइड,गठिया,सर्वाइकल, न्यूरोपैथी, किडनी का रोग,लिवर का रोग, मानसिक रोग इत्यादि की तो एक गोली भी मौजूद नहीं।

इसके बाद डॉक्टर बिष्ट ने महानिदेशालय में होने वाली अनर्गल, अनुर्वर मीटिंग नैक्ससबाजी और सालों से जमे हुए निष्क्रीय सरकारी डॉक्टरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीजी ऑफिस की मीटिंग की एक वीडियो वायरल हो रही है। देहरादून सीएमओ और महानिदेशक के बीच जो गोपनीय बातचीत होनी चाहिए थी - क्योंकि मामला एक संवैधानिक माननीय से संबंधित था- उस मीटिंग के बाहर से आए सीएमओ, कोरोना के नोडल ऑफिसर इत्यादि स्टाफ के सामने बिना शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के बड़ी बेअदबी से डिस्कस किया गया। उन्होंने कहा कि जब महानिदेशालय मे इतनी घोर अनुशासनहीनता व्याप्त हो तो IAS ऑफिसर को DG Health बनाने की मांग जायज लगती है। पूर्व में हम IAS ऑफिसर के DG बनने का विरोध करते आए हैं- मगर अब नहीं करेंगे क्योंकि महानिदेशालय अशिष्टता, फूहड़ता और कार्मिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन कर रह गया है।

महानिदेशालय में विशेषज्ञ चिकित्सक जमे हुए हैं जिनको अस्पतालों में बैठकर ग्राउंड रियलिटी का सामना करना चाहिए। इसके उलट ये डॉक्टर निदेशालय में समान की खरीदफरोस्त और कर्मचारियों के ट्रांसफरपोस्टिंग के भ्रष्टाचार का कुचक्र बनाकर अड्डा डाले हुए हैं, और दिन भर वहा से अस्पतालो में कार्यरत डॉक्टरों को विभिन्न तरीकों से डराते और जलील करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के छीछोरेपन का तो यह हाल है कि एक रिटायर्ड सीएमओ जिनकी पेंशन भी भ्रष्टाचार के चलते कुछ समय तक रुकी रही वे अब अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से अपने अधीनस्थ रहे डॉक्टरों और स्टाफ के विरुद्ध RTI डाल रहे हैं जो कि अधिकारी बनने वाले डॉक्टरों की अनैतिक मनमानी का एक और सबूत है। महानिदेशालय द्वारा मरीजों की दवाएं और उपकरण मुहैया कराने के बजाय अर्नगल बैठके करना तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और सचिवालय को गुमराह करते रहने की प्रवृत्ति से प्रतीत होता है कि - महानिदेशालय को IAS ऑफिसर डीजी ही संभाल सकता है क्योंकि ऐसे वायरल वीडियो प्रकरण और मरीजों के इलाज में विघ्न पैदा करते रहने की अव्यवसायिक कार्यप्रणाली से यह सिद्ध हो गया है कि डॉक्टर निदेशालय की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम ही नहीं है। डॉक्टरी का पेशा अतिमानवीय और जोखिम भरा है। डॉक्टरों और मजबूर रोगियों के बीच महानिदेशालय को दीवार नहीं दरवाजा बन कर खड़ा रहना होगा। अन्यथा भविष्य उस दीवार को गिरा देगा।

साइबर अपराध पर पुलिस मुख्यालय हुआ सजग - एक्सपर्ट ने बताये बचाव के उपाय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पुलिस मुख्यालय में साईबर अपराधों के सम्बन्ध में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में पुलिस उपाधीक्षक साईबर क्राईम देहरादून अंकुश मिश्रा ने विभिन्न प्रकार के साईबर क्राइम एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी दी

कार्यशाला में बताया गया कि साईबर अपराध क्या होते हैं एवं वे किस धारा के अन्तर्गत आते हैं। इसके बाद विभिन्न साईबर अपराधों पर प्रस्तुतीकरण एवं वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। कार्यशाला में बैंक से सम्बन्धित साईबर अपराध, क्यू0आर0 कोड स्कैम, व्हाट्सएप हैक, ओ0एल0एक्स फ्राड, के0वाई0सी0 फ्रॉड, हनी ट्रैपिंग, डुप्लीकेट एप, ऑनलाईन लोन स्कैम, के0बी0सी0 फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, ए0टी0एम0 फ्रॉड, सेक्सटार्शन, कम्प्यूटर सम्बन्धी फ्रॉड, आदि के सम्बन्ध में एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में अवगत कराया गया। इसके अलावा ऑनलाईन सर्च, फेक न्यूज शेयर करने सम्बन्धी सावधानियों के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

वर्कशॉप में साइबर अपराध से सम्बन्धित पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिए गए। चर्चा के अन्त में सभी को सम्बोधित करते हुए अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने बताया कि साईबर अपराधों की प्रकृति के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। परम्परागत साईबर अपराध के स्थान पर नये-नये साईबर अपराध हो रहे है और ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। भविष्य में ऐसी उपयोगी कार्यशालाऐं बडे स्तर पर आयोजित की जायेगी। इसके अलावा किसी भी वित्तीय साईबर फ्राड होने पर 1930 पर कॉल करने हेतु सभी आम नागरिक को जागरूक करने की अपील की गई। कार्यशाला में उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा साईबर अपराधों में अब तक की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी दी गयी।

कार्यशाला में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस संचार- अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- वी मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ - अजय सिंह भी उपस्थित रहे।

सड़कों का कार्य समय पर पूरा हो वरना बड़ा आंदोलन होगा : राजकुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून की राजपुर रोड से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने देहरादून नगर के डीएल रोड, आर्य नगर, छिब्बर मार्ग, करनपुर, नालापानी रोड के क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कों और अव्यवस्थित तौर पर हो रहे पाइपलाइन डलवाने के कार्य का भ्रमण किया । नगर के कई प्रमुख क्षेत्रों में बीते लंबे समय से सड़कों की मरम्मत का कार्य अटका पड़ा है एवं पाइप लाइन डालने का काम भी धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण क्षेत्र वासियों को पानी की समस्या एवं दैनिक दिनचर्या में आवाजाही को लेकर कई समस्याओं से होकर गुजरना पड़ रहा है।

पूर्व विधायक का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा सड़कों की मरम्मत एवं पाइपलाइन कार्य को एक बेहतर कार्य प्रणाली के साथ निश्चित समय के भीतर पूर्ण करने की मांग उठाई जा रही है परंतु विभाग द्वारा इस कार्य को लेकर कोई भी दिलचस्पी ना दिखाने के कारण यह कार्य लंबे समय से अटका पड़ा है। पूर्व विधायक राजकुमार ने क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर औचक भ्रमण किया और क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर देहरादून जिलाधिकारी के समक्ष मांगे रखी। जिसमें स्पष्टतः बताया गया कि जगह-जगह खुदी हुई सड़कें क्षेत्र के लोगों के आवागमन में आए थे मुश्किलें उत्पन्न कर रही हैं, क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए चलने टहलने लायक जगह भी नहीं रह गई है एवं स्थानीय बच्चे व राहगीर आए दिन खुदे हुए गड्ढों में गिरकर हादसों का शिकार हो रहे हैं।

पूर्व विधायक राजकुमार ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से अवगत कराया एवं बताया कि लंबे समय से संबंधित विभाग को इन सभी घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही थी एवं समय-समय पर मांग उठाई जा रही थी कि यह कार्य शीघ्र पूर्ण हो परंतु आपस में कोई तालमेल न होने के कारण विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार ने जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागों को चेताया कि यदि निर्धारित समय के भीतर यह कार्य पूर्ण ना हुए तो उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।

सिंथेटिक पनीर के गोरखधंधे पर डीएम डॉ आर राजेश कुमार का हंटर, एफडीए की बड़ी कार्रवाई

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

सिंथेटिक पनीर सामग्री एवं खाद्य सामग्री में मिलावट पर आ रही शिकायतों पर बड़ी और सख्त कार्यवाही की हिदायत जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जान और सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नही जाएगा।

इसी मकसद के लिए जिलाधिकारी नेजिला खाद्य संरक्षा अधिकारी देहरादून पी सी जोशी को चेकिंग अभियान चलाकर मिलावट खोरी पर कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए।

जिस के क्रम में कार्यवाही करते हुए जिला खाद्य सुरक्षा टीम के सदस्यों द्वारा आज बड़ी कामयाबी हासिल की। अभियान के तहत तीन टीमें शहर के अलग-अलग स्थानों में गठित की गई थी जिसमें एक टीम उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र रावत के नेतृत्व में सहारनपुर रोड भंडारी बाग एरिया में वाहनों की चेकिंग कर रही थी एवं दूसरी टीम मे जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी सी जोशी के नेतृत्व में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र एवं तीसरी टीम मसूरी डायवर्शन पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे एफडीए विजिलेंस से संजय नेगी आदि वाहनों में निगरानी कर रही थी, नेहरू कॉलोनी फवारा चौक से पनीर से भरी गाड़ी निकली जिसको टीम द्वारा रोका उसकी प्राथमिक जांच व पूछताछ में पता चला कि उसमें 4 कुंटल सिंथेटिक पनीर था वह सहस्त्रधारा रोड में एक दूसरे प्राइवेट कार से मसूरी भेजने की तैयारी थी दूसरी टीम उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में भंडारी बाग सहारनपुर रोड क्षेत्र में थी जहां पर एक गाड़ी में लगभग 5 कुंटल सिंथेटिक पनीर गाड़ी के भीतर पाया गया गाड़ी मालिक

का नाम इरशाद था और उसमें भी रखा पनीर अनहाइजीनिक एवं सिंथेटिक था वह भी सिंथेटिक पनीर को मसूरी तक पहुंचाना चाह रहा था लेकिन अधिकारियों द्वारा उक्त दोनों वाहनों को नगर निगम के हरिद्वार रोड में स्थित नगर निगम के कूड़ा डंपिंग जोन पहुंचाया और जेसीबी की सहायता से नगर निगम कर्मचारियों द्वारा लगभग 9 कुंटल सिंथेटिक पनीर एक गड्ढे में दबा दिया पनीर मावा के पांच नमूने क्वालिटी जांच हेतु गवर्नमेंट लैब रुद्रपुर भेजे है फूड सेफ्टी विभाग द्वारा नकली पनीर रोकथाम अभियान लगातार जारी रहेगा।

जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने खाद्य सुरक्षा की टीम एवं संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि सिंथेटिक सामग्री एवं मिलावट खोरों पर कड़ी निगरानी बनाये रखें तथा बाहर से आ रही सामग्रियों की तलाशी लेना सुनिश्चित करें। संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आम जनमानस के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ न कर सके।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी सी जोशी ने बताया कि सहारनपुर मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों से कुछ व्यक्तियों द्वारा रिफाइंड आयल लो फैट मिल्क पाउडर आदि से पनीर तैयार कर उसे सस्ते दामों में कुछ डेरियों रेस्टोरेंट्स होटल्स मे प्राइवेट गाड़ियों में सप्लाई किया जा रहा था पर्यटक सीजन एवं शादियों के सीजन के कारण आज काल दून मसूरी मे पनीर की डिमांड बढ़ गई है जिसके कारण सस्ते दाम में कुछ रेस्टोरेंट डेरी एवं और वेडिंग प्वाइंट कैटरर्स सस्ता होने के कारण उसको खरीद रहे थे।

टीम में उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत, पीसी जोशी, संजय तिवारी योगेंद्र पांडे रमेश सिंह मंजू रावत एफडीए विजिलेंस उप निरीक्षक जगदीश रतूड़ी , संजय नेगी योगेंद्र आदि उपस्थित थे।

संपादकीय

खालिस्तान पर सुलगा पटियाला

पंजाब के पटियाला शहर में खालिस्तान का मुद्दा क्यों उठा? श्री काली माता का मंदिर निशाने पर क्यों था? ये व्यापक जांच के सवाल हैं, क्योंकि पहले भी खालिस्तान पर पंजाब के विभिन्न हिस्से सुलगते और जलते रहे हैं। खालिस्तान आज एक लंबा अतीत हो चुका है। आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच टकराव तब भी नहीं हुआ था, जब खालिस्तान की मांग उग्र थी और आतंकवाद का दौर था। पंजाब का मानस कभी भी 'सांप्रदायिक' नहीं रहा। खालिस्तान ने जो ज़ख्म दिए थे, वे कभी के भर चुके हैं। पंजाब में खालिस्तान किसी को भी नहीं चाहिए। खालिस्तान समर्थन या विरोध के आज कोई मायने नहीं हैं। तो फिर अचानक पटियाला में हिंदू और सिख-निहंग चेहरे एक-दूसरे के विरोध में क्यों आ गए? तलवारें भी चमकाई गईं। पथराव भी किया गया। ऐसा लगा मानो दोनों पक्ष एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं! खुफिया सूत्रों का दावा है कि उसने सप्ताह भर पहले ही चेता दिया था कि टकराव हो सकता है! पुलिस चौकन्नी क्यों नहीं हुई? खुफिया रपट मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी सौंपी गई होगी! यदि वह पंजाब के बजाय कहीं और प्रवास पर थे, तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को रपट दी गई होगी! बुनियादी सवाल कानून-व्यवस्था के प्रति चिंतित और सचेत होने का है। पंजाब में सक्रिय शिवसेना (बाल ठाकरे) ने खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने की योजना बनाई थी। पंजाब में कई तरह की शिवसेनाएं हैं-शिवसेना समाजवादी, शिवसेना राष्ट्रवादी, शिवसेना हिंदू भैया, शिवसेना अखंड भारत। इनका महाराष्ट्र वाली शिवसेना से कोई सरोकार नहीं है, यह पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने स्पष्ट किया है। शुरुआती जांच में 32 सिख और 8 हिंदू संगठनों के नेताओं की भूमिका सामने आई है। धरपकड़ की जा रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड वजिंदर सिंह परवाना को कहा जा रहा है। इलाके के आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी, थानेदार और अन्य पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री राज्य के पुलिस महानिदेशक से नाराज़ बताए जा रहे हैं। क्या उस स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी? बहरहाल हमने खालिस्तान का खौफनाक और जानलेवा दौर देखा है। पंजाब के शहरों की तंग गलियों से खाड़कुओं को, नंगी तलवारें और रिवॉल्वर, बंदूक के साथ, भागते देखा है। हम तत्कालीन 'सुपर कॉप' केपीएस गिल के आभारी हैं कि उनके नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने ही खालिस्तान आंदोलन के घुटने तोड़ दिए थे। भिंडरावाला सरीखे आतंकी को ढेर कर दिया था। खालिस्तान आंदोलन ने ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्याएं की थीं। लिहाजा अब कोई भी सोच या साज़िश हो, हम खालिस्तान को करवट लेते नहीं देख सकते। पंजाब का चौतरफा नुकसान हुआ है। आज पंजाब की नई सरकार की अग्निपरीक्षा है, आम आदमी पार्टी को प्रचंड, एकतरफा और ऐतिहासिक जनादेश दिया गया है, लिहाजा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हररोज़ अग्निपरीक्षा है। पंजाब सरहदी राज्य है। चीन और पाकिस्तान की सीमापार से निगाहें हमारे पंजाब पर रहेंगी। यदि पंजाब में नशे की तस्करी या हथियारों की सौदागीरी हुई है, तो सरहद पार से ही कराई जाती रही हैं। पंजाब के संदर्भ में जरा-सी भी ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकपरस्त आतंकवाद अब भी ज़िंदा है।

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कान्फ्रेंस की बतायी विधिक उपलब्धि

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखण्ड में विधिक क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखण्ड द्वारा विगत 5 वर्षों में विधिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू करते हुए स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढाकर 299 कर दी तथा वर्तमान में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व लम्बित प्रकरण (3 साल की अवधि से ज्यादा) को पूर्ण करते हुए 05 नयी परियोजनाएं विगत वर्षों में जिला न्यायालयों के निर्माण इत्यादि में पूर्ण किया। उत्तराखण्ड ने अपना पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर तैयार किया है। जिसे केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसके तहत केन्द्र पोषित योजना (CSS) इस वित्तीय वर्ष में रू0 80 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित की गई है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करते हुए एक टेक्निकल अधिकारी के सापेक्ष वर्तमान में 26 टेक्निकल अधिकारी कार्यरत हैं।

सभी को सुचारू रूप से निःशुल्क न्यायिक सेवा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से सभी 13 जिलों में 13 सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नियुक्त किये। साथ ही सभी 13 जनपदों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की है। उत्तराखण्ड द्वारा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाली सुविधा के संबंध में नियमावली माह दिसम्बर 2021 में अधिसूचित कर दी गई है। उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में 02 वाणिज्यिक न्यायालय शुरू कर दिए गये हैं तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का भी संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। देश में सर्वप्रथम वृद्ध, बीमार एवं न्यायालय आने में असमर्थ व्यक्तियों की गवाही अंकित करने के लिए उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 13 मोबाइल न्यायालय वैन की सुविधा प्रारम्भ की गई है। जिससे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही अंकित की जा रही है।

प्रदेश में कुल 67858 लोगों के भौतिक सत्यापन हुए : पुलिस मुख्यालय

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चारधाम यात्रा और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने 10 वर्षों से उत्तराखण्ड में कार्यरत एवं निवास कर रहे और रेड़ी/ठेली लगाने वालों तथा किरायदारों आदि का भौतिक सत्यापन कराए जाने का अभियान 21 अप्रैल, 2022 से चलाया था , जो 10 दिन तक राज्य में सघन अभियान के तौर पर चलाया गया। जिसमें प्रदेश में कुल 67858 लोगों के भौतिक सत्यापन किये गये। सत्यापन के दौरान प्रकाश में आए कुल 2526 संदिग्ध व्यक्तियों में से 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार एवं शेष के विरूद्ध पुलिस एक्ट के अन्तर्गत व अन्य निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।सत्यापन अभियान रूटीन रूप में जारी रहेगा।

मैं भी एक मजदूर हूँ : पुष्कर सिंह धामी, सीएम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ''विश्व श्रमिक दिवस'' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने विभिन्न संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को शुभकामना देते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए हमारे श्रमिक भाई नये भारत के निर्माण का कार्य करते हैं। देश की प्रगति और खुशहाली में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले सभी श्रम योगी सम्मान के पात्र है। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमारे करोड़ों मजदूर भाई-बहनों की मेहनत और लगन के सम्मान के लिए समर्पित है। वे एक बेहतर और समृद्ध भारत की नींव तैयार कर रहे हैं, वे सही अर्थों में हमारे राष्ट्र-निर्माता हैं। 'श्रमेव जयते' के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार अपने कठिन परिश्रम और संकल्प से भारत को विश्व में अग्रणी बनाने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया के मजदूरों की एकजुटता के आहवान मात्र से काम चलने वाला नहीं है। इस सदी की आवश्यकताएं और स्थितियां अलग हैं। ''लेबर्स यूनाइट द वर्ल्ड'' इस सदी का मंत्र हो सकता है। इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। हमारे श्रमिक भाईयों में दुनिया को जोड़ने की ताकत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती, जो पांच करोड़ परिवारों को छूती हो। हमने श्रम कानूनों में अनेक बदलाव किए हैं। इसके तहत कभी मात्र 15, 50 या 100 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले श्रमिकों को हमारी सरकार ने अब न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत आठ अहम श्रम कानूनों को एक कर उनके

सरलीकरण का काम किया गया। आज हर श्रमिक को एक विशेष लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया ताकि उसकी पहचान बन जाए और उसे अवसर मिलें। साथ ही एक नेशनल सर्विस पोर्टल भी बनाया गया है, ताकि श्रमिक और नियोजक के बीच तालमेल हो सके। इसके अलावा बोनस सम्बन्धी कानून में भी बदलाव कर कामगारों को लाभ पहुंचाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लेबर्स यूनाइट द वर्ल्ड' का नारा, मैं मजदूर नंबर-1 हूं का नारा दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी खुद को एक मजदूर मानते हैं, उन पर उत्तराखंड के लोगों के प्यार का कर्ज है।

उत्तराखंड के विकास से लोगों का कर्ज चुकाने का उनका भरसक प्रयास है। पूर्व की सरकारों ने गरीबी हटाने के लिये नारे बहुत लगाये गये, योजनाएं भी बनीं लेकिन वह गरीब के घर को नहीं बल्कि मतपेटियों को ध्यान में रखकर बनायी गयीं। इस देश से गरीबी तभी जाएगी, जब गरीब को गरीबी से लड़ाई लड़ने की ताकत मिलेगी।

इसके लिये उसे शिक्षा, रोजगार, घर, बिजली, पेयजल उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजदूरों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस दौरान केबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा श्रमिकों के हित में उठाये गये कदमों तथा उनके कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून आर. राजेश कुमार, नगर आयुक्त के साथ ही बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे।

देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी है यात्रा : सतपाल महाराज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों बेहद सतर्क और गंभीर नजर आ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों और हर जिम्मेदार महकमे को उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि राज्य में आने वाला प्रत्येक धार्मिक यात्री और पर्यटक राज्य के लिए बेहद अहम और खास है। ऐसे में उसे हर तरह की सुविधा और सहूलियत देना अतिथि देवो भव की भावना को व्यक्त करना है। कोरोना के बाद रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने जिस तरह से उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन कराया है ऐसे में यह बड़ी चुनौती है कि पर्यटन विभाग और उत्तराखंड सरकार अपने अतिथियों का सत्कार और आदर करें। जिससे प्रदेश की आर्थिकी और लोगों के रोजगार में बेहतर लाभ हो सके । पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऐसे अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है जो इन जिम्मेदारियों में हीला हवाली करते हैं और विभागीय मंत्री और सरकार के आदेशों को नजरअंदाज कर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेते हैं।

सतपाल महाराज ने यात्रा के दौरान सभी विभागों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए और कहा की अधिकारी, कर्मचारी ₹अतिथि देवो भवः₹ की भावना से काम करें।

आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था की प्रतीक चारधाम यात्रा 2022 प्रारंभ होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा के कुशल संचालन के लिए सभी विभागों को चौकन्ना रहने के आदेश दिये गये हैं।

प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई प्रातः 6.25 और श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 8 मई रविवार को 6 बजकर 15 मिनट पर खुलेंगे। जबकि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को पूर्वाह्न 11.15 बजे और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 मई को ही अपराह्न 12.15 बजे खुलेंगे। पवित्र गुरूद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी एवं लोकपाल तीर्थ के कपाट रविवार 22 मई को खुलेंगे।

श्री महाराज ने कहा कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से 2 मई प्रातः 9 बजे केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में प्रवास के बाद 3 मई को गुप्तकाशी से 8 बजे प्रातः फाटा पहुँचेगी। 4 मई को फाटा से प्रातः 8 बजे श्री गौरामाई मंदिर गौरीकुंड, 5 मई को गौरीकुंड से प्रातः 6 बजे भगवान की पंचमुखी डोली श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि श्री बदरीविशाल की देवडोली 6 मई को प्रातः9 बजे श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ से आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी सहित तेल कलश गाडू घड़ा के साथ श्री बदरीनाथ धाम के रावल जी, मंदिर समिति के आचार्य एवं डिमरी पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ योगध्यान बदरी पहुंचकर वहीं प्रवास करेगी।

उन्होने कहा कि 7 मई को भगवान बदरी विशाल की डोली योग बदरी पांडुकेश्वर से प्रातः आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, रावल जी सहित देवताओं के खजांची श्री कुबेर जी एवं भगवान के सखा उद्धव जी, तेल कलश गाडू घड़ा पांडुकेश्वर से प्रातः 9 बजे श्री बदरीनाथ धाम को प्रस्थान करेगी।

पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा देवभूमि के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी है। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा को सफल बनाने का प्रयास हम सब को मिलकर करना है। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालू इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं।

उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी ₹अतिथि देवो भवः₹ की भावना के साथ तत्परता से कार्य करें। अपने सेवा भाव से सभी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक यात्री को हर संभव सहायता प्राप्त हो।

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा